कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002. Email ID-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक :– 224 राँची, दिनांक :– 09.3.2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंगः–

1. **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC-DFA-I दिनांक 22.08.2019**
2. **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC-DFA-II दिनांक 22.08.2019**
3. **क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची का पत्रांक 1284 दिनांक 26.07.2021, 1526 दिनांक 24.08.2021 एवं 314 दिनांक 22.02.2022**
4. **इस कार्यालय का पत्रांक 1272 दिनांक 21.10.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन प्रस्ताव पर भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र– 1 एवं 2 के द्वारा की गयी पृच्छाएँ का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 1284 दिनांक 26.07.2021 एवं संशोधित प्रतिवेदन पत्रांक 1526 दिनांक 24.08.2021 द्वारा प्राप्त हुई। उक्त अनुपालन में कतिपय त्रुटियाँ रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 1272 दिनांक 21.10.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पृच्छा की गयी, जिसका निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची के पत्रांक 314 दिनांक 22.02.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है।

प्रतिवेदनानुसार निराकरण निम्नवत् प्रतिवेदित किया जाता है :–

(क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC-**DFA-I** दिनांक 22.08.2019 द्वारा 8 बिन्दुओं का निराकरण :–

<table>
<tr><th>S.No.</th><th>GoI Query</th><th>Reply</th></tr>
<tr><td>I</td><td>State Govt. shall attach necessary certificate that the area is free from encroachment & encumbrance.</td><td>इस संबंध में सूचित करना है कि प्रस्तावित वन भूमि (84.35 हे0) free from encroachment & encumbrance है एवं 42.37 हे0 जंगल–झाड़ी के संबंध में अंचल अधिकारी, खेलारी के पत्रांक 48(II) दिनांक 21.01.2022 द्वारा free from encroachment & encumbrance प्राप्त है (अनु0–1)
पूर्व में प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित स्थल की विवरणी निम्नवत् था :–
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>ग्राम/मौजा</th><th>रकवा</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>नवाडीह</td><td>60 हे0</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>हेसालौंग</td><td>40 हे0</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>करकट्टा</td><td>40 हे0</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>चेलिया</td><td>60 हे0</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>तरंगा</td><td>55 हे0</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुलः–</td><td>255 हे0</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		जिसे परिवर्तन करते हुए नया स्थल प्रस्तावित किया गया है। संशोधित नया प्रस्तावित क्षतिपूरक वनरोपण की विवरणी निम्नवत् है :– <table><tr><th>क्र0सं0</th><th>ग्राम/मौजा</th><th>रकवा</th></tr><tr><td>1.</td><td>हातमा</td><td>70 हे0</td></tr><tr><td>2.</td><td>कोटारी</td><td>103.50 हे0</td></tr><tr><td>3.</td><td>मायापुर</td><td>80 हे0</td></tr><tr><td colspan="2">कुलः–</td><td>253.50 हे0</td></tr></table> संशोधित स्थल का क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन (Annex-A3) एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र (Annex-A4) DGPS (Annex-A1) एवं KML (Annex-A2) की प्रति संलग्न है।
II	State Govt. shall submit necessary certificate to confirm whether the site selected for non forest use land also compensatory afforestation is important from Religious/ Archological point of view or not	इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण से सक्षम पदाधिकारी से निर्गत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Archological Survey of India की प्रति संलग्न की गई है। **अनुलग्नक–B** प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अंचल अधिकारी, खेलारी ब्लॉक द्वारा निर्गत site selected for non forest use land also compensatory afforestation is important from Religious point of view से संबंधित पत्र संलग्न किया है। **अनुलग्नक–C**
III	Status of safety zone may be clarified by State Govt.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन किया गया है। **अनुलग्नक–D**
IV	Cost Benefit Ratio shall be calculated as per MoEF&CC guideline dated 01.08.2017.	प्रयोक्ता अभिकारण द्वारा अनुपालन किया गया है। **अनुलग्नक–E**
V	State Govt. shall provide details about the gaps/shortfall observed in the process of reclamation of the mined area by CCL in other mines within the State.	प्रयोक्ता अभिकारण द्वारा अनुपालन किया गया है। **अनुलग्नक–F**
VI	State Govt. shall furnish status of areas for which as reported there are approvals of forest area obtained in 1996 & 2009.	1996 से 2009 तक अपयोजित वनभूमि की विवरणी निम्नवत् है :– 1. के0डी0एच0 101.41 हे0 जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8–79/90 एफ0सी0 (Vol-i) दिनांक 01.07.1996 द्वारा प्राप्त है। 2. के0डी0एच0 28.95 हे0 जिसकी स्वीकृति भारत सरकार के पत्रांक 8–79/90 एफ0सी0 (Vol-i) दिनांक 26.10.2009 द्वारा प्राप्त है। जो प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 199 दिनांक 04.01.2021 के कंडिका संख्या–6 में वर्णित है।
VII	State Govt. may further clarify if \the user agency had paid NPV for entire forest area within the project/lease area as per different guidelines of MoEF&CC or not	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा entire forest area के लिए एन0पी0भी समर्पित किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा के0डी0एच0 126.72 हे0 के लिए कुल 79326720.00 रु0 समर्पित किया गया है। जो प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक 199 दिनांक 04.01.2021 के कंडिका संख्या–7 में वर्णित है।
VIII	State Government shall prepare a comprehensive proposal for diversion of entire forestland under the provisions of FCA 1980 within the project/lease area	Comprehensive proposal for version of entire forest land की प्रति संलग्न की गई है। **अनुलग्नक–H**

(ख) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC-**DFA-II** दिनांक 22.08.2019 द्वारा की गयी पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, परन्तु वह satisfactory नहीं है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, Indian Forest Act, 1927 तथा Forest Conservation Act, 1980 के संबंध में व्याख्या की गयी है, जो कि निम्नवत् है :–

Sl .No	Query	Reply
1	2	3
1	Is there any provision of lease area in CBA 1957?	MMDR Act के तहत् किसी भी खनिज के खनन् पट्टा देने हेतु खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार सक्षम प्राधिकार है। खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 2542 दिनांक 24.08.2006 (छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक– क) उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया है :– 1. राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972/73 एवं Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि पर सी0सी0एल0 को खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड से खनन पट्टा लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रस्तुत उक्त अधिनियमों के अंतर्गत सी0सी0एल0 (Deemed Lessee) है। 2. दि मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 के नियम 24(A)(6) के अनुसार यदि सी0सी0एल0 का नवीकरण आवेदन लम्बित है तो खनन पट्टे की अवधि विस्तारित की गई समझी जायेगी। पुनः खान एवं भूतत्व विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत पत्रांक खा0नि0 (विविध)–195/2012–2438/एम0 दिनांक 27.11.2012 (छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक– ख) द्वारा निम्नांकित प्रतिवेदित है जो स्वतः स्पष्ट है :– "विभागीय पत्रांक–ख0 नि0 विविध/11/2011–127/एम0, राँची दिनांक 31.01.2011 द्वारा सरकार के उप सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचित किया गया है कि Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 के तहत् अधिग्रहीत भूमि पर कोयला का खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। विभागीय पत्रांक–ख0नि0(विविध) 80/2012–1696/एम0, दिनांक 25.08.2012 द्वारा सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, राँची को सूचित किया गया है कि Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहीत क्षेत्र के लिए अलग से खनन पट्टा स्वीकृत/नवीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।" खान एवं भूतत्व विभाग को उपरोक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 के तहत् अधिग्रहित भूमि के लिये खनन् पट्टे की आवश्यकता नहीं है।
2	Can project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyse the fait accomplii situation as reffered by Hon'ble supreme court in their Lafarge Umiam v/s union of India case in 2011.	Yes, the whole project area for which mining plan is approved by competent authority shall be taken as single lease area to analyse the fait accomplii situation as reffered by Hon'ble Supreme Court in their Lafarge Umiam v/s Union of india case in 2011 but with following all the guidelines / orders/explanations issued by Government of India/ Hon'ble Supreme Court in the matter related to Forest Conservation Act 1980.

3	Can forest land be acquired under CBA 1957?	The Land Acquisition Act was enacted in 1894 for acquiring surface right for any public purpose or for a company. Later on in 1957 in order of economic interest of India greater public control over the Coal Mining industry and its development by providing for the acquisition by the State of unworked land containing or likely to contain coal deposits or rights in or over such land by enacting special Land Acquisition Act called "The Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957". Indian Forest Act was enacted in 1927 to manage and control forest in the country. Both of the above mentioned acts are Special Acts. No where in the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, it is mentioned that forest land as notified in Indian Forest Act, 1927 can be acquired. More over Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 is to gain control over coal bearing areas and to acquire surface rights which does not include forest. Government of India enacted Forest Conservation in 1980 which provide special provision for regulating Non forestry use of Forest land. Before 1980 Forest land diversion was under the purview of State Government and after 25th Oct, 1980 it came under the perview of Central Government Hence it is very clear that Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 does not have any provision far acquiring right over forest. All land acquisition acts were enacted to aquire surface rights after duly compensating rights of the person/persons having interest over the land. Under any Land Acquisition Act Government aquires rights of private individual except Government land or forest land, for which Government has propriotory rights. Government having soverign rights on such lands, is not required to determine their own rights. In 1971, to make this provision clear, Government of India amended Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 and a new clause 18-A was inserted which reads as below :- "Not withstanding anything contained in this Act, where any land or any rights in or over land belonging to a State Government (other than the rights under a mining lease granted or deemed to have been granted by the State Government to any person) vest in the Central Government under section 10 or in a Government Company under section 11, the Central Government or the Company, as the case mey be, may pay to the State Government such sum of money as would have been payable as royalty by a lessee had such land or rights been under a mining lease granted by the State Government." After insertion of above mentioned clause in Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, it has been absolutely clear that if Government land is acquired then they have to compensated on the similar pattern of private land. Even this amendment does not talk about Forest land.
4	What procedure shall be adopted legally to restore back the reclaimed forest land after completion of mining (which was acquired through CBA 1957) to forest department for uniform management.	As power of denotifying Forest Land before the enactment of Forest Conservation Act, 1980 vested with the State Government hence any land denotified by the State Government can not be taken back. But if any land diverted by the State Government before 1980 but not broken till 25th Oct 1980 then its use will attract provisions of Forest Conservation Act, 1980. Any Forest Land diverted before 1980 and broken before 1980 shall attract provisions of Forest Conservation Act, 1980 after its lease period as envisaged in Mines and Minerals (Development and Regulation) Act is over. All such Forest land which attracts provisions of Forest Conservation Act, 1980 shall be handed over to Forest Department after completion of period of Mining Plan as approved by the Competent Authority and reclamation as envisaged in the Reclamation Plan. This Forest land shall remain as forest land in revenue records as well as in Forest records and a separate document shall be maintained where such diverted lands are recorded along with period of diversion.

अतः क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की 3 प्रतियाँ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

संचिका पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक :– अनुपालन प्रतिवेदन 3 प्रतियों में

विश्वासभाजन

8/3

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

8-3-22